AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का विकासः नीतियाँ, चरण और जन–भागीदारी

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. सुधांशु कुमार
ग्राम हरनाथपुर, पोस्ट + थाना मैरवा
सिवान, बिहार, भारत

शोध सार

यह पत्र बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की विकास यात्रा का विस्तृत विश्लेषण करता है, जिसमें ठोस आँकड़ों और केस स्टडी के माध्यम से परिणामों का समर्थन किया गया है। इसमें इन उद्योगों के क्रमिक विकास के प्रमुख चरणों, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और रणनीतियों, और इस प्रक्रिया में जन–भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की गहनता से जाँच की गई है। अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज –2025, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और कृषि रोड मैप जैसी सरकारी कार्य योजनाएं, उद्यमियों की बढ़ती रुचि के साथ मिलकर इन उद्योगों के वर्तमान परिदृश्य को आकार दे रही हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2,181 करोड़ का निवेश और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में बिहार का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस क्षेत्र की तीव्र प्रगति को दर्शाता है। यह पत्र बिहार के कृषि–औद्योगिक विकास के पीछे के रणनीतिक प्रयासों, नीति कार्यान्वयन और सार्वजनिक सहभागिता के बीच के जटिल संबंधों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

मुख्य शब्द

कृषि–आधारित उद्योग, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना, खाद्य प्रसंस्करण, सरकारी नीतियाँ, सतत् विकास.

प्रस्तावना

बिहार की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि पर टिकी है, जिसमें राज्य का लगभग 77 प्रतिशत कार्यबल इसी क्षेत्र में लगा हुआ है। यह क्षेत्र राज्य के सकल मूल्य वर्धन (GSVA) में लगभग 19.9 प्रतिशत का योगदान देता है। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि इस कृषि प्रधान आधार को एक औद्योगिक शक्ति में बदलना राज्य के आर्थिक उत्थान के लिए सर्वोपरि है। कृषि उत्पादों का केवल उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है; उनका प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन (value addition) रोजगार सृजन, आय में वृद्धि और ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस संदर्भ में, कृषि आधारित उद्योगों का विकास एक रणनीतिक अनिवार्यता बन जाता है। यह पत्र इन उद्योगों के 'क्या' और 'क्यों' से आगे बढ़कर 'कैसे' पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य उन प्रक्रियाओं, नीतियों और सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता का विश्लेषण करना है जिन्होंने बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास पथ को आकार दिया है, और यह दर्शाना है कि कैसे नीतिगत हस्तक्षेप और जमीनी स्तर की पहल इस परिवर्तन को गति दे रही है।

सारणी 1: बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था का अवलोकन

संकेतक	आँकड़ा
कृषि में कार्यरत् कार्यबल	77 प्रतिशत
GSVA में कृषि का योगदान	19.9 प्रतिशत
सीमांत किसानों का प्रतिशत	91 प्रतिशत से अधिक
अनुमानित वार्षिक हानि (अनाज)	4,500 करोड़
अनुमानित वार्षिक हानि (फल और सब्जियां)	2,000 करोड़

1. कृषि आधारित उद्योगों का क्रमिक विकास

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसे ऐतिहासिक और संरचनात्मक बदलावों के माध्यम से कई चरणों में देखा जा सकता है:

- **प्रारंभिक चरण:** पारंपरिक प्रसंस्करण प्रारंभ में, ये उद्योग काफी हद तक पारंपरिक, असंगठित और स्थानीयकृत थे। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय खपत के लिए चावल और दाल मिलें, आटा चक्कियां और तेल घानियां शामिल थीं। ये इकाइयाँ छोटे पैमाने पर काम करती थीं, उनकी प्रौद्योगिकी आदिम थी और उनका बाजार सीमित था। उनका मुख्य उद्देश्य केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा करना था, न कि बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन।
- **संगठित क्षेत्र का उदय:** चीनी और जूट का प्रभुत्व बीसवीं सदी में, विशेष रूप से ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, चीनी और जूट जैसे संगठित उद्योगों का विकास हुआ। यह विकास मुख्य रूप से उत्तर बिहार के गन्ना और जूट उत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित था। एक समय था जब 1950 के दशक के मध्य तक भारत के कुल चीनी उत्पादन का 25 प्रतिशत हिस्सा बिहार से आता था। इन बड़े कारखानों ने औद्योगीकरण की नींव रखी, लेकिन उनका विकास कुछ विशेष क्षेत्रों और फसलों तक ही सीमित रहा, जिससे राज्य के अन्य कृषि–समृद्ध क्षेत्रों को लाभ नहीं मिल सका।
- **आधुनिक चरण:** खाद्य प्रसंस्करण और विविधीकरण हाल के दशकों में, विशेष रूप से राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रोत्साहन के साथ, ध्यान आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण की ओर स्थानांतरित हुआ है। अब पारंपरिक फसलों के अलावा मक्का, मखाना, फल और सब्जियों पर आधारित उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। बिहार की कृषि शक्ति इसकी विविधता में निहित है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 2: प्रमुख फसलों का उत्पादन और राष्ट्रीय रैंक

फसल / उत्पाद	उत्पादन में हिस्सेदारी / रैंक
लीची	भारत में सबसे बड़ा उत्पादक (71 प्रतिशत)
मखाना	भारत में सबसे बड़ा उत्पादक (85 प्रतिशत+)
सब्जियां	भारत में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक
फल	भारत में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक
मक्का	66.6 प्रतिशत वृद्धि (2020–21 से 2023–24)
चीनी (ऐतिहासिक)	भारत के उत्पादन का 25 प्रतिशत (1950 के दशक)

यह चरण प्रौद्योगिकी, मानकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाजार लिंकेज पर केंद्रित है, जो पारंपरिक प्रसंस्करण से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

2. विकास नीति एवं वर्तमान स्तर

वर्तमान परिवेश में, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की नीति एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती

है। सरकार की रणनीति केवल वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है जो निवेश को आकर्षित करे और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दे।

नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध प्रचुर कच्चे माल का लाभ उठाना और फसल के बाद के नुकसान को कम करना है। एक अनुमान के अनुसार, उचित प्रसंस्करण और भंडारण के अभाव में केवल अनाज में रू. 4,500 करोड़ और फलों और सब्जियों में रू. 2,000 करोड़ का वार्षिक नुकसान होता है। इस आर्थिक नुकसान को कम करना और इसे औद्योगिक लाभ में बदलना नीति का केंद्र बिंदु है।

इस नीतिगत बदलाव के परिणामस्वरूप, निवेश के माहौल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हाल ही में एक खाद्य प्रसंस्करण निवेशक सम्मेलन में, राज्य सरकार ने रू. 2,181 करोड़ के निवेश के लिए 14 आशय पत्रों (LoIs) पर हस्ताक्षर किए, जिससे 4,175 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पिछले 10 महीनों में, कुल रू. 38,500 करोड़ के 238 समझौता ज्ञापनों (MOUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। हालांकि, समग्र विकास का स्तर अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। उद्योग मुख्य रूप से प्राथमिक प्रसंस्करण पर केंद्रित हैं, और मूल्य श्रृंखला में गहरे एकीकरण की कमी है फिर भी, सरकारी नीतियों ने विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है, और इसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं।

3. सरकारी नीतियाँ एवं कार्य योजनाएँ

सरकार ने कृषि–औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई प्रमुख राज्य और केंद्र–स्तरीय नीतियां और कार्य योजनाएं लागू की हैं, जिनका प्रभाव नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी 3: सरकारी नीतियां और उनका प्रभाव

योजना / पहल	प्रमुख आँकड़ा / विवरण
खाद्य प्रसंस्करण में हालिया निवेश	रू. 2,181 करोड़ (4,175 रोजगार अपेक्षित)
PMFME योजना कार्यान्वयन	देश में प्रथम स्थान (10,296 ऋण स्वीकृत)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना	रू. 10 लाख तक की वित्तीय सहायता (रू. 5 लाख अनुदान)
PMKSY योजना	9 परियोजनाएं स्वीकृत (मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन)
कुल निवेश प्रस्ताव (पिछले 10 महीने)	रू. 38,500 करोड़ के 238 समझौता ज्ञापन

- **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025:** यह राज्य की प्रमुख औद्योगिक नीति है, जो निवेशकों को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके तहत, उद्यमियों को रू. 40 करोड़ तक की ब्याज छूट, 30 प्रतिशत तक की पूंजीगत सब्सिडी, और शुद्ध एसजीएसटी की 300 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति जैसे लाभ दिए जाते हैं।
- **मुख्यमंत्री उद्यमी योजना:** यह योजना अनुसूचित जाति / जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को रू. 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें रू. 5 लाख अनुदान (सब्सिडी) और रू. 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होते हैं।
- **कृषि रोड मैप (2023–2028):** 2008 में शुरू हुए कृषि रोड मैप की श्रृंखला में यह चौथा संस्करण है, जिसे 18 अक्टूबर, 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। पिछले रोड मैप के परिणामस्वरूप धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दोगुनी हो गई है। चौथे रोड मैप का उद्देश्य फसल विविधीकरण, मूल्यवर्धन, कृषि–प्रसंस्करण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देकर इस गति को और तेज करना है।
- **केंद्रीय योजनाएं (PMKSY and PMFME):** केंद्र सरकार की योजनाएं भी बिहार में कृषि–उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत, राज्य में मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी

गई है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के कार्यान्वयन में बिहार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए देश में पहले स्थान पर रहा है। इस योजना के तहत 10,296 आवेदकों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए, जो छोटे उद्यमियों को औपचारिक बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

4. जन–भागीदारी एवं रूझान

औद्योगिक विकास केवल सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं करता; इसमें जन–भागीदारी की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिहार में इस संबंध में एक सकारात्मक और उत्साहजनक रुझान देखा जा रहा है।

स्थानीय उद्यमी अब पारंपरिक व्यवसायों से आगे बढ़कर खाद्य प्रसंस्करण जैसे नए और आधुनिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी सरकारी योजनाओं से प्रेरित होकर, युवाओं और महिलाओं में अपना उद्यम शुरू करने की रुचि अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है।

इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। FPOs छोटे और सीमांत किसानों (जो बिहार के 91 प्रतिशत से अधिक किसान हैं) को संगठित करके उन्हें बेहतर बाजार पहुंच, मोलभाव की शक्ति और प्रसंस्करण गतिविधियों में सीधे भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण चंपारण कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (CHKPCL) है, जिसके COVID-19 महामारी के दौरान किए गए कार्यों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 4: FPO केस स्टडीः CHKPCL (COVID–19 के दौरान)

गतिविधि	परिणाम
हस्तक्षेप	20,697 किलो सब्जियां और 5,026 किलो दालें बेची गईं
लाभान्वित किसान	लगभग 400 किसान
मुख्य प्रभाव	बिचौलियों का उन्मूलन और किसानों को सीधा लाभ

यह जमीनी स्तर पर भागीदारी का एक शक्तिशाली मॉडल है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। यह रुझान ऊपर से नीचे (top-down) के विकास मॉडल से हटकर एक अधिक समावेशी, सहभागी और टिकाऊ दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है।

निष्कर्ष

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का विकास एक धीमी लेकिन स्थिर यात्रा रही है, जिसे अब रणनीतिक सरकारी नीतियों और बढ़ती सार्वजनिक भागीदारी से प्रबल बल मिल रहा है। पारंपरिक प्रसंस्करण से आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण की ओर बदलाव, जो राज्य की विशाल कृषि संपदा (जैसे लीची, मखाना और सब्जियां) पर आधारित है, राज्य की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है।

आँकड़े इस परिवर्तन की पुष्टि करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हालिया रू. 2,181 करोड़ का निवेश, PMFME जैसी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में राज्य का शीर्ष प्रदर्शन, और CHKPCL जैसे FPOs की सफलता की कहानियाँ, सभी एक सकारात्मक दिशा का संकेत देते हैं। हालांकि चुनौतियां, जैसे कि अधूरी मूल्य श्रृंखला और बुनियादी ढांचे की कमी, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाया गया नीतिगत ढांचा (BIIPP–2025) और उद्यमियों तथा किसान समूहों का बढ़ता उत्साह एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इस विकास की अंतिम सफलता सरकार, निजी क्षेत्र और किसानों के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर करेगी। यदि नीति, निवेश और जन–भागीदारी का यह तालमेल बना रहता है, तो बिहार निस्संदेह अपनी कृषि क्षमता को एक स्थायी औद्योगिक शक्ति में बदलने में सफल होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों लोगों के लिए समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।

संदर्भ सूची

1. बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला (2024) बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, अध्याय 7, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, पटना।
2. बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला (2025, अप्रैल) बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, अध्याय 15, दृष्टिकोण और नीति, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, क्लेयरटैक्स, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, क्लेयरटैक्स, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, पटना।
3. कृषि विभाग, बिहार सरकार, हमारे बारे में, डि बी टी कृषि बिहार, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना, https://state.bihar.gov.in/agriculture, Accessed on 15/11/2025.
4. कृषि विभाग, बिहार सरकार, चौथा कृषि रोडमैप 2023–28, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. जीकेटुडे (2025) बिहार 2025 में पीएमएफएमई योजना लागू करने में अग्रणी, जीकेटुडे, नई दिल्ली, https://www.gktoday.in, Accessed on 15/11/2025.
6. द टाइम्स ऑफ इंडिया (2025, 12 सितंबर) औद्योगिक विकास ने बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि को पीछे छोड़ा, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, https://timesofindia.indiatimes.com, Accessed on 15/11/2025.
7. इंडिया ब्रीफिंग (2024) बिहार में निवेश, भारतः एक राज्य प्रोफाइल, इंडिया ब्रीफिंग, देज़ान शिरा एंड एसोसिएट्स, गुरुग्राम, https://www.india-briefing.com.news.investing-in-bihar-india-state-profile, Accessed on 15/11/2025.
8. इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज (2024) बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, ई–सारांश, लोक सेवा संस्थान, पटना, https://www.scribd.com, Accessed on 15/1/2025.
9. शर्मा, आर. (2025) बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि और संभावनाएं, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज,* 7(2), 45–52।
10. कौशल्या फाउंडेशन (2023) सीएचकेसीपीएलः एक किसान उत्पादक संगठन, बिहार में ग्रामीणों के साथ जुड़ा, कौशल्या फाउंडेशन, नई दिल्ली।
11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (2024) राज्य प्रोफाइलः बिहार, भारत सरकार, नई दिल्ली, https://www.mofpi.gov.in, Accessed on 15/11/2025.
12. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2023) बिहार की कृषिः सांख्यिकीय रूपरेखा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (2023) मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. न्यूज़ ऑन एआईआर (2024) बिहार सरकार ने नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया, ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली, https://newsonair.gov.in, Accessed on 15/11/2025.
15. पालित, पी. (2023–2028) बिहार का चौथा कृषि रोडमैप, बिहार सरकार, पटना।
16. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (2023) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं उद्यमिता, भारत सरकार, नई दिल्ली, https://www.pmuy.gov.in, Accessed on 15/11/2025.

17. प्रेस सूचना ब्यूरो (2021, 23 मार्च) बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली, https://www.pib.gov.in, Accessed on 15/11/2025.

18. प्रेस सूचना ब्यूरो (2023, 18 अक्टूबर) राष्ट्रपति द्वारा बिहार के चौथे कृषि रोडमैप का शुभारंभ, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।

19. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (2023) बिहार बजट विश्लेषण 2023–24, पीआरएस भारत, नई दिल्ली, https://prsindia.org, Accessed on 15/11/2025.

20. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (2025) बिहार बजट विश्लेषण 2025–26, पीआरएस भारत, नई दिल्ली, https://prsindia.org, Accessed on 15/11/2025.

21. रूमी, एफ. (2024, 3 दिसंबर) रू. 2,181 करोड़ निवेश से बिहार के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 4,175 नौकरियाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, https://timesofindia.indiatimes.com, Accessed on 15/11/2025.

22. ग्रामीण बिहार (2024) कृषि रोडमैप–प्ट एवं एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावित भूमिका, ग्रामीण बिहार, पटना।

23. शंकर आईएफएस पॉलिटेक्निक (2024) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, शंकर आईएफएस पॉलिटेक्निक, चेन्नई।

24. गेटस्वाइप (2025) मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार, गेटस्वाइप, https://www.getswipe.in, Accessed on 15/11/2025.

25. द टाइम्स ऑफ इंडिया (2024) बिहार में निवेश पर चर्चाः उद्योग मंत्री, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, https://timesofindia.indiatimes.com, Accessed on 15/11/2025.

26. द टाइम्स ऑफ इंडिया (2025, 9 मई) पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में बिहार सबसे आगे, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, https://timesofindia.indiatimes.com, Accessed on 15/11/2025.

––==00==––